S. No.	States/UTs	Total funds sanctioned and released during 1995-96	Total funds sanctioned and released during 1996-97	Total funds sanctioned and released during 1997-98
14.	Manipur	92.07	34.16	39.00
15.	Meghalaya	85.61	59.47	25.63
16.	Mizoram	801.41	378.36	943.64
17.	Nagaland	25.70	8.43	32.50
18.	Orissa	642.02	270.26	282.00
19.	Punjab	344.39	287.04	391.82
20.	Rajasthan	258.77	421.74	77.51
21.	Sikkim	170.29	149.89	158.04
22.	Tamil Nadu	848.73	386.38	457.99
23.	Tripura	14.63	6.90	20.66
24.	Uttar Pradesh	923.96	1033.06	497.14
25.	West Bengal	589.18	457.47	384.38
26.	Andaman & Nicobar Islands	60.49	3.66	3.99
27.	Chandigarh	8.06	3.52	1.20
28.	Dadra & Nagar Haveli	1.44	0.00	0.00
29.	Daman & Diu	1.44	0.50	0.00
30.	Delhi	368.21	109.21	70.24
31.	Lakshadweep	2.70	1.19	0.00
32.	Pondicheery	9.26	7.03	5.53
33.	Others*	1674.55	2016.88	2964.74

*Funds released to agencies other than State Government and State Nodal Agencies underbiogas, improved chulha, biomass gasifier and small hydro power programmes.

Status of Planning Commission

*238. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Planning Commission is a Constitutional body like the Finance Commission or it is an extra-constitutional body formed after the constitution was adopted;

(b) if it is a constitutional body, why its formation, authority and jurisdiction are not clearly specified in the constitution like the Finance Commission;

(c) whether National Development Council (NDC) is also an extra-constitutional body like the Planning Commission; and

(d) if not, what is the constitutional status and role of NDC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) Planning Commission was set up by the Cabinet Secretariat Resolution dated the 15th March, 1950 and is not a constitutional body like the Finance Commission.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The National Development Council was set up by a Resolution of the Cabinet Secretariat dated August 6, 1952 to strengthen and mobilise the effort and resources of the nation in support of the Five Year Plan, to promote common economic policies in all vital spheres and to ensure the balanced and raped development of all parts of the country. The Government considered the

recommendations of the Administrative Reforms Commission and reconstituted the National Development Council vide Cabinet Secretariat Resolution dated the October 7, 1967. The redefined functions of the NDC are as follows:

(i) to prescribe guidelines for the formulation of the National Plan, including the assessment of resources for the Plan;

(ii) to consider the National Plan as formulated by the Planning Commission;

(iii) to consider important questions of social and economic policy affecting national development;

(iv) to review the working of the Plan from time to time and to recommend such measures as are necessary for achieving the aims and targets set out in the National Plan, including measures to secure the active participation and co-operation of the people, improve the efficiency of the administrative services, ensure the fullest development of the less advanced regions and sections of the community and, through sacrifice borne equally by all citizens, build up resources for national development.

कपास का उत्पादन

*239. **श्री रामजीलाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक भागों, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में गत चार वर्षों से कपास की फसल को कीड़ा लगने के कारण पैदावार बहुत कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय समस्या के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) देश के वैज्ञानिकों द्वारा इस संबंध में क्या कार्य किया जा रहा है तथा क्या आगामी बुआई मौसम तक बीमारी-रहित बीज उपलब्ध करा दिए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) राज्यों में 1994-95 से 1997-98 तक कपास के उत्पादन और उपज संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (**नीचे देखिये**) वर्ष 1997-98 में देश के कुछ भागों में औसत उपज में कमी हुई है। तथापि, उपज में इस कमी का कारण केवल कीटों के आक्रमण को ही नहीं माना जा सकता।

(ख) कपास की उत्पादकता में सुधार के लिए किसानों को शिक्षित करने हेतु किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. कपास के बीजों की रोगरोधी किस्मों की बोआई के साथ-साथ उर्वरकों तथा सिंचाई का इष्टतम मात्रा में प्रयोग और जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था करना।

2. संस्तुत कीटनाशी दवाओं का सही मात्रा में प्रयोग करना।

(3) एकीकृत कीट प्रबंध कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव-नियंत्रण एजेन्टों, फैरोमोन, जैव कीटनाशकों आदि का प्रयोग।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और देश के राज्य-कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत वैज्ञानिक कपास के बीजों की रोग-रोधी किस्में विकसित करने में लगे हैं। सी०एन०एच०-1012, सी०एन०एच०-123, आर०एस०-2013 और आर०एस०-992 नामक चार समजीनियों को पत्तियां मुड़ने के रोग का प्रतिरोधी पाया गया है। इन जीवाणु-समूहों का कोयम्बटूर स्थित केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन की बे-मौसमी नर्सरी में बहुलीकरण किया जा रहा है ताकि आगामी मौसम में उष्ण स्थान वाले क्षेत्रों में इनका और आगे परीक्षण तथा चयन किया जा सके। रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के साथ-साथ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कपास में पत्तियां मुड़ने के रोग के वायरस जैसी बीमारियों का अध्ययन करने वाली अनुसंधान परियोजनाओं पर भी विचार कर रही है। आगामी बोआई मौसम के लिए एल०आर०के०-516, एल०आर०ए०-5166, आर०जी०-8, संकर-10, एल०एच०-1556, एफ-846, एफ-1378, एफ-1054 और एल०डी०-327 जैसी रोगरोधी किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध हैं।